Seventeenth Loksabha

an>

Title: Demand to provide 4G connectivity in Post Offices and to connect the post offices wi Core Banking System.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): सभापति महोदय, मेरा प्रश्न इंटरनेट सुविधा से संबंधित है। हमारे दे में डेढ़ लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं। वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष बजट में घोषणा की है।

माननीय सभापति : आपका विषय नौसेना युद्ध पोत ट्राफी के बारे में है?

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सभापति महोदय, विषय चेंज कर दिया है।

माननीय सभापति : आपको बताना चाहिए था।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सभापति महोदय, हमारे देश में डेढ़ लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं। वित्त मंत्री जी इस वर्ष के बजट में घोषणा की है कि सभी को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्राहक अप अकाउंट्स ऑनलाइन एक्सेस कर सकेंगे और पोस्ट ऑफिस में मनी ट्रांसफर दूसरे बैंकों से भी कर पाएंगे भारत सरकार की योजना सराहनीय है, लेकिन वर्तमान में सारे पोस्ट ऑफिस में मूलभूत सुविधा जैसे इंटरने का अभाव है। जहां इंटरनेट है वहां स्पीड बहुत कम है, इससे ग्राहक जिसमें किसान, वरिष्ठ नागरिक औ ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनको असुविधा होती है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स और कार्य अ ऑनलाइन होते हैं। केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए इंटरनेट की आवश्यक है। देश में पोस्ट ऑफिसेज की कनेक्टिविटी दो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से की जाती है, प्राइमरी रूप बीएसएनएल और एमटीएनल और सीफी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स द्वारा की जाती है 12.10.2020 के जारी किए गए मेमोरेंडम के अनुसार पोस्ट ऑफिस इंटरनेट सुविधाओं का इस्तेमाल कर के लिए सिर्फ बीएसएनएल और एमटीएनएल के नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। मंत्रालय द्वारा दिए ग आंकडों के अनुसार एमटीएनएल और बीएसएनएल का वर्ष 2020-21 में 64 हजार 700 लिंक फेल्योर हैं सीफी के 15 हजार 134 लिंक फेल्योर हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल का 4जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह संचालित नहीं हुआ है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि पोस्ट ऑफिस में इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव के कारण कार्य बाधि होता है, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान गाइडलाइन्स में संशोधन करक पोस्ट ऑफिस को ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वह ट्रांसपेरंट बिडिंग प्रॉसेस से अन्य नेटवर्क सर्वि प्रोवाइडर्स की सेवा ले सके जो बेहतर कनैक्टिविटी दे सकते हैं। निर्धारित समय सीमा में सब पोस्ट ऑफिसे में 4जी कनैक्टिविटी का प्रावधान किया जाए ताकि भविष्य में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से काम करने की घोषण की जा सके।